



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I-खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 23, 2008/आषाढ़ 2, 1930

No. 220]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 2008/ASADHA 2, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(फरफरोधी एवं संबद्ध शुल्क प्रविशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2008

जांच शुरुआत

विषय: यूरोपीय संघ (ईयू) के मूल के अधिकांश वहाँ से निर्यातित थियोनाइट क्लोराइड के आयात संबंधी फरफरोधी जांच की शुरुआत।

1. जांच शुरुआत

फा. सं. 14/1/2008—डीजीएडी.—यतः मै. ग्वालियर केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि., मुम्बई और ट्रांसपेक इंडस्ट्रीज लि., बड़ोदरा (जिन्हें एतद्विषयात् आवेदक कहा गया है) ने वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर फरफरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतद्विषयात् नियम कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्विषयात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें ईयू (जिसे एतद्विषयात् संबद्ध देश/क्षेत्र कहा गया है) के मूल के अधिकांश वहाँ से निर्यातित थियोनाइट क्लोराइड (जिसे एतद्विषयात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के फाटन का आरोप लगाया गया है और संबद्ध वस्तु पर फरफरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए फरफरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

2. विचाराधीन उत्पाद

विचाराधीन उत्पाद थियोनाइट क्लोराइड है जिसका रासायनिक सूत्र SOCl_2 है और जिसे सल्फरस ऑक्सीक्लोराइड, सल्फरस डाइक्लोराइड, सल्फिनाइल क्लोराइड, सल्फिनाइल डाइक्लोराइड, डाइक्लोरोसल्फोक्सिड आदि नामों से भी जाना जाता है। थियोनाइट क्लोराइड एक प्रतिक्रियात्मक रासायनिक अधिकर्मक है जिसका प्रयोग क्लोरीनेशन संबंधी प्रक्रियाओं में होता है। कमरे के तापमान एवं दाब पर यह रंगहीन आसवन-योग्य द्रव है जो 140° से. से अधिक तापमान पर विघटित हो जाता है।

ऋणात्मक रूप से सक्रिय सामग्री के रूप में लिथियम के साथ सकारात्मक रूप से सक्रिय सामग्री के रूप में थियोनाइट क्लोराइड का प्रयोग लिथियम-थियोनाइट बैटरियों के अंदर होता है। अन्य रासायनिक यौगिकों या सामग्रियों के उत्पादन हेतु अधिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। सैन्य उपयोगों में थियोनाइट क्लोराइड का उपयोग जी-सीरीज नर्व एजेंट्स के उत्पादन की "डाई-डाई" पद्धति में होता है। एक आंतरिक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन के जरिए फार्मेक्सइलिक एसिड्स को एसोइल क्लोराइड्स में और अल्कोहलों को तदनुसंगी अल्काइल क्लोराइड्स में परिवर्तित करने में व्यापक रूप से इसका उपयोग होता है। इस उत्पाद की बिक्री थोक तथा पैकड रूपों में होती है। इस जांच में उपर्युक्त उत्पाद को उसकी पैकेजिंग, जिसमें उत्पाद की बिक्री की गई हो, की स्थिति पर ध्यान दिए बिना सभी रूपों एवं प्रकारों में शामिल किया जाएगा।

संबद्ध उत्पाद को अध्याय 28 के तहत रखा गया है और संगत आठ अंक स्तरीय वर्गीकरण 2812.1040 है।

3. समान वस्तु

आवेदकों ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश/क्षेत्र से आयातित संबद्ध वस्तु में कोई विशेष अंतर नहीं है जिसका कीमत, प्रयोग, गुणवत्ता आदि पर कोई प्रभाव पड़ सके। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध वस्तुएँ भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के रूप में तुलनीय हैं। अतः वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उत्पादित उत्पाद को नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देश/क्षेत्र से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

4. घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति

इस जांच हेतु आवेदन मै. ग्वालियर केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि., मुम्बई और मै. ट्रॉसपेक इंडस्ट्रीज लि., वड़ोदरा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीन और कंपनियाँ हैं जिनके पास ज्ञात रूप से भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की क्षमता है, अर्थात् मै. एम्बार्को केमिकल्स प्रा. लि., गुजरात, मै. मीनाक्षी केमिकल्स प्रा. लि., बड़ौदा और मै. श्री सल्फरिक लि., अहमदाबाद। प्राधिकारी ने इन उत्पादकों की उत्पादन मात्राओं और उनके द्वारा उपर्युक्त आवेदन के समर्थन अथवा विरोध का आकलन किया है। मै. श्री सल्फरिक लि. तथा मै. मीनाक्षी केमिकल्स ने अपनी उत्पादन संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है और आवेदन का समर्थन किया है। मै. एम्बार्को केमिकल्स प्रा. लि., गुजरात ने प्रत्यक्षतः उत्पादन बंद कर दिया है और सूचना हेतु प्राधिकारी के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया है। प्राप्त सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक कंपनियाँ भारतीय उत्पादन के बड़े हिस्से का उत्पादन करती हैं। अतः, प्राधिकारी मानते हैं कि इस जाँच के प्रयोजनार्थ आवेदक नियम 5(3) के अनुसार आवेदन करने की स्थिति में हैं और नियम 2(ख) के अनुसार वे घरेलू उद्योग हैं।

5. शामिल देश/क्षेत्र

इस जांच में यूरोपीय संघ के मूल की अथवा वहाँ से आयातित वस्तु शामिल है।

6. सामान्य मूल्य

आवेदकों ने धारा 9क(1)(ग)(i) के तहत सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु यूरोपीय संघ में घरेलू बिक्री कीमतों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है। तथापि, व्यापार के स्तर तथा बिक्री की स्थितियों के बारे में पूर्ण सूचना के अभाव में उक्त आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग ने कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों तथा अन्य परिवर्तन संबंधी खर्चों के आधार पर यूरोपीय संघ में संबद्ध वस्तुओं की अनुमानित उत्पादन लागत उपलब्ध कराई है तथा पाटन की प्रारंभिक जांच के प्रयोजनार्थ

इस तथ्य पर विश्वास किया गया है। तदनुसार, प्रारंभिक जांच के प्रयोजनार्थ धारा 9क(ग)(ii)(ख) के संदर्भ में सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया गया है।

7. निर्यात कीमत

उत्पाद को बल्क एवं पैकड स्वरूप में बेचा जा रहा है। पैकड एवं बल्क स्वरूपों में संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का अनुमान आंकड़ों हेतु गौण स्रोतों तथा डीजीसीआई एण्ड एस के आंकड़ों के सारांश से एकत्रित सौदे-वार आयात आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है। भारतीय औसत निर्यात कीमत का निर्धारण ईयू से आयातों की कुल मात्रा एवं मूल्य पर विचार करके किया गया है। कारखाना द्वार निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री भाड़े, पत्तन प्रभारों, बीमा एवं अंतर्देशीय पत्तन प्रभारों इत्यादि में समायोजन किया गया है।

8. पाटन मार्जिन

आवेदकों द्वारा प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि संबद्ध देश/क्षेत्र में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य, भारत को निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है, जिससे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश/क्षेत्र से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है। इस प्रकार अनुमानित पाटन मार्जिन सकारात्मक है तथा न्यूनतम स्तर से अधिक है।

9. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में संबद्ध देश/क्षेत्र से पाटित आयातों की मात्रा एवं मूल्य तथा घरेलू उद्योग को क्षति से संबंधित विभिन्न मानदण्डों के बारे में सूचना उपलब्ध कराई है। समग्र अर्थों में तथा उत्पादों की मांग के संबंध में आयातों की मात्रा में वृद्धि, बाजार हिस्से में गिरावट, कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास, लाभ में गिरावट, निवेश पर आय तथा नकद प्रवाह जैसे मानदण्डों में समेकित रूप से प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश/क्षेत्र से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

10. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की सटीकता एवं पर्याप्तता से संतुष्ट होकर निर्दिष्ट प्राधिकारी पाते हैं कि संबद्ध देश/क्षेत्र से संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद है। तदनुसार, प्राधिकारी किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव यदि कोई हो, का निर्धारण करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि जिसे यदि लागू किया जाए तो यह घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच प्रारंभ करते हैं।

11. जांच की अवधि (पीओआई)

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) में 12 महीने अर्थात् 1 जनवरी, 2007 से 31 जनवरी, 2007 की अवधि शामिल है। तथापि कति जांच अवधि में वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 तथा जांच की अवधि शामिल होगी।

12. सूचना उपलब्ध कराना

यूरोपीय संघ में निर्यातकों, यूरोपीय आयोग को उनके दिल्ली के शिष्टमंडल के माध्यम से, इस जांच से संबंधित भारत के ज्ञात आयातकों एवं उपभोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने तथा निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनशेखी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार
कमरा सं. 287बी, उद्योग भवन
नई दिल्ली- 110011

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित ढंग से नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकती है।

13. समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों एवं आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें यह सूचना भेजे गए पत्र की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर भेजनी होगी। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

14. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

नियम 6(7) के संदर्भ में हितबद्ध पार्टियों को प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना होगा। गोपनीय सूचना के अगोपनीय रुपांतर अथवा अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि दूसरी हितबद्ध पार्टियों को सूचना का अर्थ स्पष्ट हो सके। यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाली पार्टी की राय में ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तो उसके कारण का विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। तथापि, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है अथवा उसका सामान्यीकरण नहीं करना चाहता अथवा

12. Submission of information

The exporters in the European Union, the European Commission, through its delegation in Delhi, the importers and users in India known to be concerned with this investigation, the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Government of India
Room No. 287B
Udyog Bhavan
New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions, relevant to the investigation, in the prescribed form and manner within the time limit set out below:

13. Time limit

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty (40) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however, required to submit the information within (40) forty days from the date of the letter addressed to them. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

14. Submission of information on Non-confidential basis

In terms of Rule 6(7), of the Rules the interested parties are required to submit non-confidential version of any confidential information provided to the Authority. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary; a statement of reason thereof is required to be provided. However, if the Designated Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted, or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, the Designated Authority may disregard such information.

15. Use of facts available

In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

16. Inspection of public file

Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties in terms of Rule 6 (7).

R. GOPALAN, Designated Authority

conditions of sales, the said data has not been relied upon. The domestic industry has also provided the estimated cost of production of the subject goods in the European Union based on international prices of raw material and other conversion expenses, which has been relied upon for the purpose of preliminary examination of dumping. Accordingly, Normal Value has been estimated in terms of Section 9A(c)(ii)(b) for the purpose of initiation

7. Export price

The product is sold in bulk and packed form. The export prices of subject goods in packed and bulk forms have been estimated on the basis of transaction-wise import data collected from secondary data sources and summary data of DGCI&S. Weighted average export price has been determined considering the total volume and value of imports for EU. Adjustments have been made on account of ocean freight, port charges, insurance and inland port charges etc. in order to arrive at the ex-factory export price.

8. Dumping margin

On the basis of positive evidence placed by the applicants before the Authority it appears that the Normal Value of the subject goods in the subject country/territory is significantly higher than the net export price to India, indicating prima-facie that the subject goods are being dumped in the Indian market by exporters from the subject country/territory. The dumping margin so estimated, is positive and above de minimis levels.

9. Injury and causal link

The applicants have furnished information on volume and value of dumped imports from the subject country/territory and various parameters relating to injury to the domestic industry, on account of the product under consideration. Parameters, such as increase in volume of imports both in absolute terms and in relation to the demand of the products, decline in market share, price undercutting and underselling, price depression, decline in profits, returns on investments and cash flow prima-facie collectively indicates that the dumped import of the subject goods from the subject country/territory has injured the Domestic Industry.

10. Initiation of Anti Dumping Investigations

Having satisfied itself about the accuracy and sufficiency of the information submitted by the applicant domestic industry, the Designated Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods from the subject country/territory, injury to the domestic industry, and causal links between the dumping and injury exist. Accordingly, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry, in terms of the Rules 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping, if any, and to recommend the amount of antidumping duty which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

11. Period of investigation (POI)

The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation consists 12 months period from 1ST January 2007 to 31ST December 2007. The injury investigation period will, however, cover the period 2004-05, 2005-06, 2006-07 and the POI.